भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6319

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

.....

कोसी और महानंदा नदी में बाढ़ के खतरे

6319. श्री राजेश रंजनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्णिया प्रभाग के जिलों को प्रभावित करने वाली कोसी और महानंदा नदी प्रणालियों में बाढ़ के खतरे की कोई बेसिन-स्तरीय समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन जिलों में 'बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' के अंतर्गत अनुमोदित बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोसी-महानंदा बेसिन में केंद्रीय जल आयोग द्वारा संचालित हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्टेशनों और बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या बाढ़ पूर्वानुमान, जल निकासी प्रबंधन या तटबंध सुरक्षा से संबंधित किसी अवसंरचना संबंधी कमी की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्रीय सहायता से इस क्षेत्र में बाढ़ से लड़ने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): वर्ष 1986 से 2022 तक सेटेलाइट इमेजरी डेटा पर आधारित केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट 'भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का आकलन, 2024' के अनुसार, पूर्णिया डिवीजन के चार जिलों पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन 2,77,815 हेक्टेयर किया गया है।

(ख) से (ङ): बाढ़ प्रबंधन और अपरदन रोधी योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार निर्मित और कार्यान्वित की जाती है। केंद्रीय सरकार राज्यों के प्रयासों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के माध्यम से प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करके सहायता करती है।

पुर्णिया प्रभाग में 81.59 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता के साथ तीन बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं केंद्रीय प्रायोजित योजना 'बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)' के तहत पूरी की गई हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) कोसी-महानंदा बेसिन में 25 हाइड्रोलॉजिकल ऑब्ज़र्वेशन स्टेशन और 17 बाढ़ पूर्वानुमान (16 लेवल + 01 इनफ्लो) स्टेशन प्रबंधित करता है। बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकरणों से परामर्श करके स्थापित किए गए हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों को लोगों के निकासी की योजना बनाने और अन्य सुधारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्रीय जल आयोग ने वर्षा-बहाव गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिन वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है, जो सभी पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए 7 दिनों के अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान परामर्श के साथ-साथ चिन्हित किए गए स्थलों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे तक की अग्रिम समय सीमा के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है।

*****